प्रवासी भलई संगठन

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

(रिट याचिका (सी) संख्या-157/2013)

12 मार्च, 2014

[डॉ. बी. एस. चौहान, एम. वाई. ईक्बाल एवं ए. के. सिकरी, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 14,15,19,21 सपठित अनुच्छेद 38; अनुच्छेद 51-ए (ए), (बी), (सी), (ई), (ए), (आई), (जे)-निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए घृणित भाषण, राजनीतिक और धार्मिक नेता मुख्य रूप से धर्म, जाति, क्षेत्र या जातीयता पर आधारित-

रिट याचिका में इस आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है कि नफरत भरे भाषण भाईचारे के संवैधानिक विचार के खिलाफ हैं और अनुच्छेद 38 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 का उल्लंघन करते हैं और अनुच्छेद 51-ए (ए), (बी), (सी), (ई) (एफ) (आई) (जे) के तहत मौलिक कर्तव्यों का अपमान करते हैं।

माना गया: वैधानिक प्रावधान और विशेष रूप से दंडात्मक कानून "घृणास्पद भाषणों" के खतरे को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय प्रदान करते हैं- इस प्रकार, पीड़ित व्यक्ति को एक विशेष क़ानून के तहत प्रदान किए गए उपाय का सहारा लेना चाहिए- समस्या की जड़ कानूनों की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि- उनके प्रभावी कार्यान्वयन की कमी है- इसलिए, कार्यपालिका के साथ-साथ नागरिक समाज को पहले से मौजूद कानूनी व्यवस्था को लागू करने में अपनी भूमिका निभानी होगी- सभी स्तरों पर "घृणास्पद भाषणों" का प्रभावी विनियमन आवश्यक है, जैसा कि लेखकों ने किया है ऐसे भाषणों को मौजूदा दंडात्मक कानून के तहत दर्ज किया जा सकता है और सभी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा कानून एक मृत पत्र नहीं बन गया है- प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रस्ताव "सैलस रीपब्लिका सुप्रीमा लेक्स" (राज्य की सुरक्षा सर्वोच्च कानून है) के अनुरूप होना आवश्यक है- इस प्रकार, कुछ निश्चित निर्देश जारी करने के लिए याचिका दायर की जाती है जो निर्देश प्रवर्तन/निष्पादन में अक्षम हैं, उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी शक्ति के भीतर होगा यदि वह घृणास्पद भाषण दंड संहिता, 1860 के कथित लेखकों के खिलाफ स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लेता है। उपधारा- 124ए, 153ए, 153बी, 295ए, 298, 505(2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- उपधारा 123(3), 125- मैक्सिम "सैलस रीपब्लिका सुप्रेमा लेक्स"। -

मानव अधिकार:

नफरत फैलाने वाला भाषण- सरकार द्वारा उठाए गए कदम- माना गया: भारतीय कानूनी ढांचे ने इस विषय से निपटने के लिए कई वैधानिक प्रावधान बनाए हैं- इसके अलावा, केंद्र सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हमेशा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को कई तरीकों से सहायता प्रदान की है। देश में और जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार भी समय-समय पर इस संबंध में सलाह भेजती है- केंद्र सरकार ने 2008 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए संशोधित दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जो अन्य बातों के अलावा सख्त कार्रवाई का प्रावधान करते हैं। असंयमित और भड़काऊ भाषणों और बयानों से भावनाओं को भड़काने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए- दंड संहिता, 1860 धर्म से संबंधित अपराधों को दंडनीय बनाती है। इसी तरह, 'अनुसूचित जाति' और 'अनुसूचित जनजाति' के सदस्यों को जानबूझकर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने पर भी दंड दिया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत- आर.पी. अधिनियम किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को

ऐसे कृत्य को दंडनीय अपराध बनाकर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना पैदा करने से रोकता है- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, 1966 (आईसीसीपीआर) का अनुच्छेद 20(2) राष्ट्रीय, नस्लीय या धार्मिक घृणा की वकालत को रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप भेदभाव, शत्रुता या हिंसा भड़क सकती है और इसे निषिद्ध कानून के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय- नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन, 1965 (आईसीईआरडी) के अनुच्छेद 4 और 6 के अनुसार घृणा भाषण के तत्वों को प्रतिबंधित करते हैं और सदस्य राज्यों को एक उपयुक्त माध्यम से किसी भी प्रकार के घृणा भाषण को प्रतिबंधित करने वाला कानून बनाने का आदेश देते हैं। कानून की रूपरेखा-दंड संहिता, 1860- उपधारा 124 ए, 153 ए, 153 बी, 295 ए, 298, 505(2)- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- उपधारा 123(3), 125.

घृणास्पद भाषण- अदालतों का कर्तव्य- माना गया: अदालतों को घृणास्पद भाषण निषेध को निष्पक्ष रूप से लागू करना चाहिए- अदालतों को यह प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए कि क्या एक उचित व्यक्ति, जो संदर्भ और परिस्थितियों से अवगत है, अभिव्यक्ति को संरक्षित समूह को घृणा के संपर्क में लाने के रूप में देखेगा- भेदभाव को कम करने या समाप्त करने

के विधायी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अपने दर्शकों पर अभिव्यक्ति के संभावित प्रभाव को निर्धारित करना कुंजी है।

न्यायिक हस्तक्षेप: संविधान स्पष्ट रूप से शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान करता है और न्यायालय केवल उस कानून को लागू करता है जो उसे विधायिका से मिलता है- यदि कोई कानून है, तो न्यायाधीश निश्चित रूप से इसे लागू कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीश कोई कानून नहीं बना सकते हैं और उसे लागू करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं- न्यायालय इसे दोबारा नहीं लिख सकता है, कानून को नए सिरे से तैयार करना या नया नाम देना बहुत अच्छे कारण के लिए है क्योंकि इसमें कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है- हालाँकि, हाल ही में, भारत में वरिष्ठ न्यायालयों की न्यायिक सक्रियता ने बार-बार लोगों की भौंहें चढ़ा दी हैं। न्यायालय द्वारा निर्देश केवल तभी जारी किए जाते हैं जब- कानून में पूरी तरह से शून्यता आ गई है, यानी बुनियादी मानव अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सक्रिय कानून का पूर्ण अभाव- यदि किसी भी कारण से कार्यपालिका की ओर से निष्क्रियता होती है, तो अदालत ने कदम उठाया है। कानून को लागू करने के लिए अपने संवैधानिक दायित्वों के बारे में- किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए कानूनी व्यवस्था के शून्य होने की स्थिति में अदालत निरपेक्षता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकती है। जब तक विधायिका इस क्षेत्र को कवर करने के लिए उचित कानून बनाकर अपनी भूमिका निभाती है- इस प्रकार, केवल उस स्थिति में निर्देश जारी

किये जा सकते है जब निर्वाचित विधायिका की इच्छा अभी तक व्यक्त नहीं हुई हो- न्यायिक सक्रियता- न्यायिक समीक्षा।

शब्द और वाक्यांश: घृणास्पद भाषण- अर्थ और इसका प्रभाव- माना गया: घृणास्पद भाषण किसी समूह में उनकी सदस्यता के आधार पर व्यक्तियों को हाशिये पर धकेलने का एक प्रयास है- ऐसी अभिव्यक्ति का उपयोग करना जो समूह को घृणा के लिए उजागर करता है, घृणास्पद भाषण समूह के सदस्यों को उनकी नज़र में अवैध घोषित करना चाहता है बहुसंख्यक, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज के भीतर स्वीकार्यता को कम करते हैं, इसलिए घृणास्पद भाषण, व्यक्तिगत समूह के सदस्यों को परेशान करने से कहीं आगे बढ़ जाता है- इसका सामाजिक प्रभाव हो सकता है, घृणास्पद भाषण बाद में कमजोर लोगों पर व्यापक हमलों के लिए आधार तैयार करता है, जो भेदभाव से लेकर हो सकते हैं। बहिष्कार, पृथक्करण, निर्वासन, हिंसा और, सबसे चरम मामलों में, नरसंहार के लिए- घृणास्पद भाषण एक संरक्षित समूह की बहस के तहत महत्वपूर्ण विचारों पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता को भी प्रभावित करता है, जिससे हमारे लोकतंत्र में उनकी पूर्ण भागीदारी में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है।

सार्वजनिक हित की प्रकृति में तत्काल रिट याचिका को अंतर-राज्य प्रवासियों के कल्याण के लिए समर्पित एक संगठन द्वारा प्राथमिकता दी गई है, जो भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 32 के तहत असाधारण

क्षेत्राधिकार के प्रयोग की मांग कर रही है ताकि उत्पन्न होने वाली चिंताओं का समाधान किया जा सके। "घृणास्पद भाषण" इस आधार पर कि निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक और धार्मिक नेताओं द्वारा मुख्य रूप से धर्म, जाति, क्षेत्र या जातीयता पर आधारित ये "घृणास्पद भाषण" भाईचारे के संवैधानिक विचार के खिलाफ हैं और अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 का उल्लंघन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 38 के साथ और संविधान के अनुच्छेद 51-ए (ए), (बी), (सी), (ई), (एफ), (आई), (आई) के तहत मौलिक कर्तव्यों का अपमान है और इसलिए, केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है।

कोर्ट ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए

अभिनिर्धारित किया:

1. कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय "मानवाधिकार" दायित्वों को सामने लाने में सफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप "घृणास्पद भाषण" की अभिव्यक्ति को परिभाषित करने वाले मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए "घृणास्पद भाषणों" के प्रकाशन पर नियंत्रण हुआ, यह देखते हुए कि "घृणा" की परिभाषा निर्धारित की गई है *कनाडा में (मानवाधिकार आयोग) कुछ संशोधनों के साथ, "घृणा" शब्द की व्याख्या करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है जैसा कि घृणास्पद भाषण को प्रतिबंधित करने वाले विधायी प्रावधानों में उपयोग किया जाता है। तीन

मुख्य नुस्खों का पालन करना होगा। सबसे पहले, अदालतों को घृणास्पद भाषण निषेध को निष्पक्ष रूप से लागू करना चाहिए। अदालतों को यह सवाल अवश्य पूछना चाहिए कि क्या एक उचित व्यक्ति, जो संदर्भ और परिस्थितियों से अवगत है, इस अभिव्यक्ति को संरक्षित समूह को घृणा के संपर्क में लाने के रूप में देखेगा। दूसरा, विधायी शब्द "घृणा" या "घृणा या अवमानना" की व्याख्या "घृणा" और "निंदा" शब्दों द्वारा वर्णित भावना की उन चरम अभिव्यक्तियों तक सीमित होने के रूप में की जानी चाहिए। यह उस अभिव्यक्ति को फ़िल्टर करता है जो प्रतिकूल और आपत्तिजनक होते हुए भी घृणा, अवैधीकरण और अस्वीकृति के स्तर को नहीं भड़काती है जिससे भेदभाव या अन्य हानिकारक प्रभाव पैदा होने का खतरा होता है। तीसरा, न्यायाधिकरणों को अपने विश्लेषण को मुद्दे पर अभिव्यक्ति के प्रभाव पर केंद्रित करना चाहिए, अर्थात् क्या इससे लक्षित व्यक्ति या समूह को दूसरों द्वारा घृणा का सामना करने की संभावना है। व्यक्त किए जा रहे विचारों की प्रतिकूलता अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने का औचित्य साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और अभिव्यक्ति के लेखक का इरादा घृणा या भेदभावपूर्ण व्यवहार को भड़काना है या नहीं, यह अप्रासंगिक है। भेदभाव को कम करने या समाप्त करने के विधायी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अपने दर्शकों पर अभिव्यक्ति के संभावित प्रभाव को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। [पैरा 6] [465-ए-जी]

2. नफरत फैलाने वाला भाषण किसी समूह में उनकी सदस्यता के आधार पर व्यक्तियों को हाशिये पर धकेलने का एक प्रयास है। ऐसी अभिव्यक्ति का उपयोग करना जो समूह को घृणा के लिए उजागर करती है, घृणास्पद भाषण समूह के सदस्यों को बहुसंख्यकों की नज़र में अवैध ठहराने का प्रयास करता है, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज के भीतर स्वीकार्यता कम हो जाती है। इसलिए, नफरत फैलाने वाला भाषण व्यक्तिगत समूह के सदस्यों को परेशान करने से कहीं आगे बढ़ जाता है। इसका सामाजिक प्रभाव पड़ सकता है. नफरत फैलाने वाला भाषण बाद में कमजोर लोगों पर व्यापक हमलों के लिए आधार तैयार करता है, जो भेदभाव से लेकर बहिष्कार, अलगाव, निर्वासन, हिंसा और सबसे चरम मामलों में नरसंहार तक हो सकता है। नफरत फैलाने वाला भाषण एक संरक्षित समूह की बहस के तहत महत्वपूर्ण विचारों पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता को भी प्रभावित करता है, जिससे हमारे लोकतंत्र में उनकी पूर्ण भागीदारी में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है। नफरत भरे भाषणों के ऐसे विनाशकारी परिणामों को देखते हुए, भारतीय कानूनी ढांचे ने इस विषय से निपटने के लिए कई वैधानिक प्रावधान बनाए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हमेशा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को कई तरीकों से सहायता प्रदान की है और जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार समय-समय पर इस संबंध में सलाह भी भेजती है। हालाँकि, ऐसे मामलों में, चूंकि पुलिस और सार्वजनिक

व्यवस्था संविधान की 7 वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है, इसलिए घृणा फैलाने वाले भाषणों में शामिल अपराधों सहित अपराध के पंजीकरण और अभियोजन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है। [पैरा 7,10,11] [465-जी-एच; 466-ए-बी, एफ; 467- एफ-जी] रमेश बनाम भारत संघ AIR 1988 SC 775: 1988 (2) SCR 1011 पर भरोसा किया गया।

ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, 9 वां संस्करण- संदर्भित किया गया।

3.1. केंद्र सरकार ने 2008 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए संशोधित दिशानिर्देश भी जारी किए हैं जो अन्य बातों के अलावा असंयमित और भड़काऊ भाषणों और बयानों से भावनाओं को भड़काने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। "सांप्रदायिक सद्भाव पर दिशानिर्देश, 2008" जारी किए गए। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सांप्रदायिक गड़बड़ी/दंगों को रोकने और टालने का प्रयास किया जाता है और ऐसी गड़बड़ी होने की स्थिति में, इसे नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की जाती है और प्रभावित व्यक्तियों को सहायता और राहत प्रदान करने के उपाय प्रदान किए जाते हैं, जिसमें पुनर्वास भी शामिल है। निवारक/उपचारात्मक उपाय करने और प्रशासन की ज़िम्मेदारियाँ लागू करने और उन्हें लागू करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

इस मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न तौर-तरीके तैयार किए गए हैं जिनमें हितधारकों की भागीदारी पर जोर दिया गया है। दंड संहिता, 1860 की धारा 124ए राजद्रोह को दंडनीय अपराध बनाती है, यानी, जब कोई व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना का प्रयास करता है या असंतोष भड़काने का प्रयास करता है। [पैरा 12 और 13] [467-एच; 468-ए-ई]

केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य एआईआर 1962 एससी 955: 1962 सप्ल। एससीआर 769-पर निर्भर।

3.2. आईपीसी की धारा 153ए और 153बी ऐसे किसी भी कार्य को दंडनीय बनाती है जो धर्म और नस्ल आदि के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देता है या जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है। इस तरह के प्रावधान को लागू करने का उद्देश्य "विखंडनकारी सांप्रदायिक और अलगाववादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना और भाईचारे को सुरक्षित करना था ताकि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित हो सके"। निस्संदेह, धार्मिक स्वतंत्रता के साथ धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ दूसरों की धार्मिक मान्यताओं की उचित आलोचना करने की स्वतंत्रता भी हो सकती है, लेकिन जैसा कि अदालतों द्वारा बार-बार माना गया है, शक्तियों के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आईपीसी की

धारा 295 ए धर्म से संबंधित अपराधों से संबंधित है और भाषण के लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान करती है।

ऐसे लेख या संकेत जो किसी भी वर्ग के नागरिकों के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से बनाए गए हों। इसी तरह आईपीसी की धारा 298 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया कोई भी कार्य दंडनीय है। हालाँकि, IPC की धारा 295A कहीं अधिक गंभीर अपराधों से संबंधित है। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 505(2) में प्रावधान है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान देना एक दंडनीय अपराध है जिसमें तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों शामिल हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जिसे भारत में 'अस्पृश्यता' को समाप्त करने के संवैधानिक आदेश के पूरक के लिए अधिनियमित किया गया था, में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे 'दलित' समुदायों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण को दंडित करने के प्रावधान शामिल हैं। अधिनियम की धारा 7(1)(सी) किसी भी व्यक्ति या वर्ग द्वारा किसी भी रूप में 'अस्पृश्यता' की प्रथा को उकसाने या प्रोत्साहित करने पर रोक लगाती है (शब्दों द्वारा, चाहे मौखिक या लिखित रूप से, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा)। आम तौर पर व्यक्तियों या जनता की। इसी प्रकार, 'अनुसूचित जाति' और 'अनुसूचित

जनजाति' के सदस्यों का जानबूझकर सार्वजनिक अपमान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दंडित किया जाता है। आर.पी. अधिनियम की धारा 123(3), अंतर प्रदान करती है। साथ ही, कोई भी पार्टी या उम्मीदवार धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा आदि के आधार पर वोट की अपील नहीं करेगा। आर.पी.एक्ट की धारा 125 किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी या नफरत की भावना पैदा करने से रोकती है। ऐसे कृत्य को दंडनीय अपराध बनाकर भारत के नागरिक। [पैरा 14 से 18] [468-एफ-एच; 469-ए-एच]

रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1957 एससी 620: 1957 एससीआर 860 पर भरोसा किया गया।

4. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, 1966 (आईसीसीपीआर) का अनुच्छेद 20(2) राष्ट्रीय, नस्लीय या धार्मिक घृणा की वकालत को रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप भेदभाव, शत्रुता या हिंसा भड़क सकती है, इसे कानून द्वारा निषिद्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1965 (आईसीईआरडी) के अनुच्छेद 4 और 6 नफरत भरे भाषण के तत्वों को प्रतिबंधित करते हैं और सदस्य देशों को कानून के उपयुक्त ढांचे के माध्यम से किसी भी तरह के नफरत भरे भाषण को प्रतिबंधित

करने वाला कानून बनाने का आदेश देते हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विधायिका ने पहले ही ऐसी गतिविधियों में लिप्त लेखक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त और प्रभावी उपाय प्रदान कर दिया था। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता ने कानून के समान राहत की मांग की। इस न्यायालय ने लगातार यह माना है कि हमारा संविधान स्पष्ट रूप से शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान करता है और न्यायालय केवल उस कानून को लागू करता है जो उसे विधायिका से मिलता है। नतीजतन, एंग्लो-सैक्सन कानूनी परंपरा ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायाधीशों को प्रत्याशित परिणामों, निष्पक्षता या सार्वजनिक नीति के विचारों की परवाह किए बिना केवल कानून को प्रतिबिंबित करना चाहिए और न्यायाधीश कानून बनाने के लिए अधिकृत नहीं है। "यदि कोई कानून है, तो न्यायाधीश निश्चित रूप से इसे लागू कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीश कोई कानून नहीं बना सकते हैं और न ही इसे लागू करने का प्रयास कर सकते हैं।" अदालत किसी अच्छे कारण से कानून को दोबारा नहीं लिख सकती, दोबारा नहीं बना सकती या नया स्वरूप नहीं दे सकती क्योंकि उसके पास कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। कानून बनाने का अधिकार ही न्यायालयों को नहीं दिया गया है। हालाँकि, हाल ही में, भारत में उच्च न्यायालयों की न्यायिक सक्रियता ने बार-बार लोगों की भौंहें चढ़ा दी हैं। हालाँकि न्यायिक सक्रियता को संविधान के अनुसार सामाजिक बेहतरी के लिए कानून की उपयोगिता बढ़ाने की दृष्टि से मौजूदा प्रावधान की सक्रिय

व्याख्या के रूप में माना जाता है, लेकिन इसकी आड़ में अदालतें सामाजिक-आर्थिक न्याय की संवैधानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत हैं। कई मामलों में, इस न्यायालय ने क़ानूनों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए विभिन्न दिशानिर्देश/दिशा-निर्देश जारी किए, या जब यह पाया गया कि कुछ लाभार्थी प्रावधानों का अयोग्य लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था। पात्र व्यक्तियों को वैध दावों से वंचित किया जा रहा है। व्यक्ति. [पैरा 19 और 20] [470-ए-एच; 471-ए]

एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य। एआईआर 1982 एससी 149: 1982 एससीआर 365; बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ एवं अन्य। एआईआर 1984 एससी 802: 1984 (2) एससीआर 67; भारत संघ एवं अन्य. बनाम देवकी नंदन अग्रवाल एआईआर 1992 एससी 96; सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य। बनाम भारत संघ एआईआर 1994 एससी 268: 1993 (2) पूरक। एससीआर 659; विशाखा और अन्य। बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। एआईआर 1997 एससी 3011 1997 (3) सप्ली. एससीआर 404; मंडल प्रबंधक, अरावली गोल्फ क्लब एवं अन्य। वी. चंदर हस और अन्य। (2008) 1 एससीसी 683 2007 (12) एससीआर 1084; सामान्य कारण (एक पंजीकृत सोसायटी) बनाम भारत संघ एवं अन्य। (2008) 5 एससीसी 511:2008 (6) एससीआर 262; नंद किशोर बनाम पंजाब राज्य (1995) 6 एससीसी 614: 1995 (4) पूरक। एससीआर 16- पर निर्भर।

5. इस न्यायालय ने लगातार स्पष्ट किया है कि न्यायालय द्वारा निर्देश केवल तभी जारी किए गए हैं जब कानून में पूर्ण शून्यता हो गई है, यानी बुनियादी मानव अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सक्रिय कानून की पूर्ण अनुपस्थिति। यदि किसी भी कारण से कार्यपालिका की ओर से निष्क्रियता होती है, तो कानून को लागू करने के लिए अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए, अदालत ने कदम उठाया है। किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए कानूनी व्यवस्था के शून्य होने की स्थिति में न्यायालय उस समय तक दोषमुक्ति प्रदान करने की अधिकतम सीमा तय करता है, जब तक विधायिका इस क्षेत्र को कवर करने के लिए उचित कानून बनाकर अपनी भूमिका निभाती है। इस प्रकार, निर्देश केवल उसी स्थिति में जारी किया जा सकता है जहां निर्वाचित विधायिका की इच्छा अभी तक व्यक्त नहीं की गई है। इसके अलावा, अदालत को ऐसी राहत नहीं देनी चाहिए या ऐसा आदेश/निर्देश पारित नहीं करना चाहिए जो कार्यान्वयन में सक्षम न हो। [पैरा 22 और 23] [471-एफ-एच; 472-ए]

यूपी राज्य और अन्य. वी ऊपर। राज्य खनिज विकास निगम संघर्ष समिति एवं अन्य। (2008) 12 एससीसी 675: 2008 (7) एससीआर 536- पर निर्भर।

6. न्यायिक समीक्षा न्यायिक संयम के सिद्धांतों के अधीन है और इसे अन्य पहलुओं में असहनीय नहीं होना चाहिए। अनुचित कार्यों पर

उचित प्रतिबंध लगाना वांछनीय है लेकिन निषेध को कुछ प्रबंधनीय मानकों तक सीमित रखने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है और ऐसा करने में, इसमें सभी प्रकार के भाषण शामिल हो सकते हैं जिनसे बचना आवश्यक है। लंबे समय से अमेरिकी अदालतें"घृणास्पद भाषण" और संबंधित मुद्दों पर अंकुश लगाने वाले कानूनों को बरकरार रखने में संतुष्ट थीं। हालाँकि, हाल ही में, अदालतों ने गियर बदल दिए हैं जिससे असंख्य फैसलों का मार्ग प्रशस्त हो गया है जो एक प्रबंधनीय समाज के आदेश के विपरीत भाषण और अभिव्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में हैं। [पैरा 24, 25] [472-डी, ई-जी]

किंग एम्परर बनाम ख्वाजा नजीर अहमद एआईआर 1945 पीसी 18; हरियाणा राज्य एवं अन्य। वी. चौ. भजन लाल एवं अन्य। एआईआर 1992 एससी 604: 1990 (3) पूरक। एससीआर 259; अखिलेश यादव आदि बनाम विश्वनाथ चतुर्वेदी (2013) 2 एससीसी 1: 2012 (13) एससीआर 949- पर निर्भर।

ब्यूहरनैस बनाम इलिनोइस, 343 यू.एस. 250 (1952): ब्रैंडेनबर्ग बनाम ओहियो 395 यू.एस. 444 (1969); आर.ए.वी. वी. सेंट पॉल शहर 112 एस. सीटी. 2538 (1992)- संदर्भित।

7. यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है जो मनमाना, अनुचित या अन्यथा किसी वैधानिक प्रावधानों या दंड कानून का उल्लंघन

है, तो अदालत अपने सामने मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और इसमें शामिल वैधानिक प्रावधानों पर विचार करते हुए राहत दे सकती है। हालाँकि, अदालत को कोई न्यायिक रूप से असहनीय आदेश पारित नहीं करना चाहिए जो प्रवर्तन में असमर्थ हो। [पैरा 26] [473-ए-बी]

8. वैधानिक प्रावधान और विशेष रूप से दंडात्मक कानून "घृणास्पद भाषणों" के खतरे को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय प्रदान करते हैं। इस प्रकार, पीड़ित व्यक्ति को एक विशेष क़ानून के तहत प्रदान किए गए उपाय का सहारा लेना चाहिए। समस्या की जड़ कानूनों का अभाव नहीं, बल्कि कानून का अभाव है, उनके प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव। इसलिए, कार्यपालिका के साथ-साथ नागरिक समाज को भी पहले से मौजूद कानूनी व्यवस्था को लागू करने में अपनी भूमिका निभानी होगी। सभी स्तरों पर"घृणास्पद भाषणों" का प्रभावी विनियमन आवश्यक है क्योंकि ऐसे भाषणों के लेखकों पर मौजूदा दंडात्मक कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है और सभी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा कानून बेकार न हो जाए। उक्त प्रावधानों का प्रवर्तन "सैलस रीपब्लिका सुप्रिमा लेक्स" (राज्य की सुरक्षा सर्वोच्च कानून है) के प्रस्ताव के अनुरूप होना आवश्यक है। इस प्रकार, कुछ ऐसे निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका जो प्रवर्तन/निष्पादन में असमर्थ हैं, उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नफरत फैलाने वाले भाषण के कथित लेखकों के खिलाफ स्वत: संज्ञान से

कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लेता है तो यह उसके अधिकार क्षेत्र में होगा। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विधि आयोग ने यह अध्ययन किया है कि क्या चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक दल या उसके सदस्यों को अयोग्य ठहराते हुए उसकी मान्यता रद्द करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए, यदि कोई पार्टी या उसके सदस्य ऐसा कोई अपराध करते हैं , विधि आयोग भी उठाए गए मुद्दों की पूरी तरह से जांच कर सकता है और यदि वह उचित समझे तो "घृणास्पद भाषण" की अभिव्यक्ति को परिभाषित करने पर भी विचार कर सकता है और "घृणास्पद भाषणों" के खतरे को रोकने के लिए चुनाव आयोग को मजबूत करने के लिए संसद को सिफारिश कर सकता है। चाहे कभी भी दिए गए हो। [पैरा 27 और 28] [473-सी-एच; 474-ए]

प्रकरण कानून संदर्भ:

2013 एससीसी 11	उल्लेख किया गया	पैरा 6
(1990) 3 एससीआर 892	उल्लेख किया गया	पैरा 6
1988 (2) एससीआर 1011	पर निर्भर	पैरा 9
1962 सप्ली. एससीआर 769	पर निर्भर	पैरा 13
1957 एससीआर 860	पर निर्भर	पैरा 15
1982 एससीआर 365	पर निर्भर	पैरा 20

1984 (2) एससीआर 67 पर निर्भर पैरा 20

एआईआर 1992 एससी 96 पर निर्भर पैरा 20

1993 (2) सप्ली. एससीआर 659 पर निर्भर पैरा 20

1997 (3) पूरक. एससीआर 404 पर निर्भर पैरा 20

2007 (12) एससीआर 1084 पर निर्भर पैरा 20

2008 (6) एससीआर 262 पर निर्भर पैरा 20

1995 (4) सप्ली. एससीआर 16पर निर्भर पैरा 21

2008 (7) एससीआर 536 पर निर्भर पैरा 23

एआईआर 1945 पीसी 18पर निर्भर पैरा 24

1990 (3) सप्ल. एससीआर 259 पर निर्भर पैरा 24

2012 (13) एससीआर 949 पर निर्भर पैरा 24

नागरिक मूल क्षेत्राधिकार: भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

रिट याचिका (सिविल) संख्या 157/2013

मोहन जैन, सिद्धार्थ लूथरा, एएसजीएस, बसवा प्रभु पाटिल, बी.एच. मार्लापल्ले, राज सिंह राणा, अजय बंसल, मंजीत सिंह, गौरव भाटिया, सूर्यनारायण सिंह, एएजीएस, रवि चंद्र प्रकाश, पुरूषोत्तम शर्मा, त्रिपाठी, फिल्ज़ा मूनिस, मुकेश क्र. सिंह, बी. सुब्रमण्यम प्रसाद एल.एन. धीराम

शर्मा, दुर्गादत्त, संजीब पाणिग्रही, लव कुमार, नरेंद्र कुमार गोयल, सौमित्र जी चौधरी, अनिप सच्ते, अविजीत भट्टाचार्जी, गोपाल सिंह, रितु राज विश्वास, के.एन. मधुसूदनन, टी.जी. नारायणन नायर, अरुणा माथुर, यूसुफ खान (अर्पुथम, अरुणा एंड कंपनी के लिए) कीर्ति रेनू मिश्रा, अपूर्व उपमन्यु, आशा गोपालन नायर, अभिषेक कुमार पांडे, जयेश गौरव, गोपाल प्रसाद, कृष्णा सरमा, नवनीत कुमार (कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप के लिए), एस.एस. शमशेरी, भरत सूद, वरुण पुनिया, संदीप सिंह, रितेश प्रकाश यादव, हर्षवर्द्धन सिंह राठौड़, अमित शर्मा, रुचि कोहली, सी.डी. सिंह, अपूर्व कुरुप, साक्षी कक्कड़, कुलदीप सिंह, राजीव नंदा, अणुव्रत शर्मा, बालाजी श्रीनिवासन, लिज़ मैथ्यू, एम.एफ. फिलिप, समीर अली खान, एम. योगेश कन्ना, डॉ. सुधीर बिस्ला, सुमित्रा बिस्ला, रंजन मुखर्जी, सुभ्रो सान्याल, डी.के. ठाकुर, डी.एस. महरा, ऋचा पांडे, मीनाक्षी अरोड़ा, मोहित डी. राम, डी.एल. चिदानंद, आदित्य सिंघला, बी. कृष्णा प्रसाद, जे.एस. छाबड़ा, परदम सिंह, गौरव यादव, के. एनातोली सेमा, अमित कुमार सिंह, सपम विश्वजीत मैतेई, अशोक कुमार सिंह, विवेकता सिंह, नूपुर चौधरी, अनिल श्रीवास्तव, ऋतुराज विश्वास, बांसुरी स्वराज, निर्निमेश दुबे, मुकेश वर्मा, रवि प्रकाश मेहरोत्रा, उपस्थित पक्षों के लिए प्रगति नीखरा, आर. राकेश शर्मा, बी. बालाजी- उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. बी.एस. चौहान, जे. द्वारा सुनाया गया-

1. भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग की मांग करते हुए, सार्वजनिक हित की प्रकृति में, अंतर-राज्य प्रवासियों के कल्याण के लिए समर्पित एक संगठन द्वारा तत्काल रिट याचिका दायर की गई है। (इसके बाद 'संविधान' के रूप में संदर्भित) निम्नलिखित प्रार्थनाओं के माध्यम से "घृणास्पद भाषणों" के कारण उत्पन्न हुई चिंताओं का समाधान करने के लिए:

a. धर्म, जाति, क्षेत्र और जातीय आधार पर जन प्रतिनिधियों/राजनीतिक/धार्मिक नेताओं द्वारा दिए गए घृणा/अपमानजनक भाषणों को संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), 15 (धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध), 16 (सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता), 19 (भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण), 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) मौलिक अनुच्छेद 51-ए (ए), (बी), (सी), (ई), (एफ), (आई) और (जे) के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 38 के साथ पढ़े गए अधिकार का उल्लंघन घोषित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में उचित रिट, आदेश, डिक्री जारी करें और केंद्र और राज्य की ओर से कठोर निर्णयात्मक कार्रवाई के योग्य हैं।

b. धर्म, जाति, नस्ल और जन्म स्थान (क्षेत्र) के आधार पर किए गए नफरत/अपमानजनक भाषणों को जो भारत संघ के खिलाफ एकता और अखंडता को कमजोर करता हो एवं देश और गैर-भेदभाव और भाईचारे के खिलाफ संघर्ष करता है; एक अधिनियम घोषित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में उचित रिट, आदेश, डिक्री जारी करें।

c. परमादेश की प्रकृति में उचित रिट, आदेश, डिक्री जारी करें जिसमें घोषणा की जाए कि "बंधुत्व" संविधान की "बुनियादी संरचना" का हिस्सा है;

d. संघ और राज्य सरकारों द्वारा धर्म, जाति, नस्ल और जन्म स्थान (क्षेत्र) के आधार पर किए गए घृणा/अपमानजनक भाषणों के लेखकों के खिलाफ अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने वाले परमादेश की प्रकृति में उचित रिट, आदेश, डिक्री जारी करें। वैकल्पिक रूप से, भारत के क्षेत्र के भीतर दिए गए घृणा/अपमानजनक भाषणों का संज्ञान लेने के लिए इस न्यायालय के परामर्श से भारत संघ द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें लेखकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश करने की शक्ति होगी।

e. धर्म, जाति, नस्ल और जन्म स्थान (क्षेत्र) के आधार पर घृणा/अपमानजनक भाषण देने वालों को कहीं भी जनता को संबोधित करने से रोकने के लिए "गैग ऑर्डर" लगाने का अनिवार्य निर्देश देने वाले

परमादेश की प्रकृति में उचित रिट, आदेश, डिक्री जारी करें। मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत देने के लिए आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही के निपटारे तक भारत के क्षेत्र के भीतर;

f. धर्म, जाति, नस्ल और जन्म स्थान (क्षेत्र) के आधार पर नफरत/अपमानजनक भाषण देने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाहियों के 6 महीने की अवधि के भीतर त्वरित निपटान का निर्देश देने वाले परमादेश की प्रकृति में उचित रिट, आदेश, डिक्री जारी करें

g. संघ/राज्य विधानमंडल और अन्य निर्वाचित निकायों से धर्म, जाति, नस्ल और जन्म स्थान (क्षेत्र) के आधार पर दिए गए घृणा/अपमानजनक भाषणों के लेखकों की सदस्यता को आपराधिक कार्यवाही के अंतिम निपटान तक निलंबित करने का निर्देश देने वाले परमादेश की प्रकृति में उचित रिट, आदेश, डिक्री जारी करें।

h. संघ/राज्य विधानमंडल और अन्य निर्वाचित निकायों से धर्म, जाति, नस्ल और जन्म स्थान (क्षेत्र) के आधार पर नफरत/अपमानजनक भाषण देने वाले लेखकों की, यदि दोषी पाया गया; सदस्यता समाप्त करने का निर्देश देने वाले परमादेश की प्रकृति में उचित रिट, आदेश, डिक्री जारी करें।

i. भारत के चुनाव आयोग द्वारा धर्म, जाति, नस्ल और जन्म स्थान (क्षेत्र) के आधार पर नफरत/अपमानजनक भाषण देने वाले लेखकों के

राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने का निर्देश देने वाले परमादेश की प्रकृति में उचित रिट, आदेश, डिक्री जारी करें। जहां लेखक संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए(5), 123(3) और चुनाव प्रतीकों (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 धारा 16ए के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए राजनीतिक दल का नेतृत्व कर रहा है।

j. परमादेश की प्रकृति में उचित रिट, आदेश, डिक्री जारी करें जिसमें संविधान के अनुच्छेद 227, 355 के अनुच्छेद 38 के साथ पढ़े गए जनादेश के संदर्भ में राज्यों के अलावा नफरत/अपमानजनक भाषणों के लेखकों पर मुकदमा चलाने के लिए भारत संघ को समवर्ती क्षेत्राधिकार रखने का निर्देश दिया जाए। जो केंद्र सरकार की ओर से अग्रिम कठोर कार्रवाई होनी चाहिए;

k. संविधान के अनुच्छेद 51-ए (ए), (बी) (सी) (ई), (एफ), (आई) और (जे) के तहत मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए भारत संघ और संबंधित राज्यों को निर्देश देने वाले परमादेश की प्रकृति में उचित रिट, आदेश, डिक्री जारी करें। भारत के नागरिकों के बीच राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाकर ऐसी अन्य उचित रिट या निर्देश जारी करें जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और न्याय के हित में उचित और न्यायसंगत माना जा सके।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बसवा प्रभु एस. पाटिल ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत हमारे संविधान की योजना के अनुरूप है क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए "घृणास्पद भाषण" मुख्य रूप से धर्म, जाति, क्षेत्र या जातीयता पर आधारित धार्मिक नेता भाईचारे के संवैधानिक विचार के खिलाफ हैं और संविधान के अनुच्छेद 38 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 का उल्लंघन करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 51-ए (ए), (बी), (सी), (ई), (एफ), (आई) (जे) के तहत मौलिक कर्तव्यों का अपमान करते हैं और इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। इस विषय से संबंधित मौजूदा कानून "घृणास्पद भाषणों" के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। घृणा/अपमानजनक भाषण को किसी भी दंडात्मक कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसे भाषणों के लेखक को प्रशंसा दी जाती है और उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है। ऐसी तथ्य-स्थिति में, यह न्यायालय केवल मूक दर्शक नहीं बना रह सकता है, बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिशानिर्देश जारी करनी होगी, जो उक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं क्योंकि मौजूदा कानूनी ढांचा "घृणास्पद भाषणों" के खतरे को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, इस न्यायालय को उपरोक्त राहत देनी चाहिए।

3. श्री सिद्धार्थ लूथरा, विद्वान एएसजी, श्री राजीव नंदा, श्री गौरव भाटिया, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान एएजी, सुश्री आशा गोपालन नायर, श्री गोपाल सिंह, सुश्री रुचि कोहली, श्री सी.डी. सिंह और संबंधित राज्यों की ओर से उपस्थित अन्य सभी स्थायी वकीलों ने प्रस्तुत किया है कि विषय वस्तु से निपटने के लिए विभिन्न वैधानिक प्रावधान हैं और इसमें शामिल मुद्दा उक्त वैधानिक प्रावधानों को लागू करने का प्रश्न है और कोई भी व्यथित व्यक्ति इसे रख सकता है। ऐसी स्थिति में कानून क्रियान्वित होता है।

विद्वान एएसजी श्री सिद्धार्थ लूथरा ने आगे प्रस्तुत किया है कि चुनावी सुधारों के हिस्से के रूप में राजनीति को अपराधमुक्त करने का मुद्दा 2011 की रिट याचिका (सी) संख्या 536 में इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और उक्त मामले में, इस न्यायालय ने कुछ निश्चित निर्णय लिए हैं। मुद्दे और मामले को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद "आर.पी.एक्ट" के रूप में संदर्भित) के संबंध में विषय का अध्ययन करने के लिए भारत के विधि आयोग को भेजा गया है और आदेश के तहत भारत सरकार को उचित सुझाव (रिपोर्ट) दे सकता है। दिनांक 16.12.2013 और, इस प्रकार, श्री लूथरा ने सुझाव दिया है कि यदि कानून में कुछ कमी है, तो इस न्यायालय को सुपर-विधायिका के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि विधि आयोग को आगे का अध्ययन करने और

अपनी रिपोर्ट इस पर विचार/स्वीकृति हेतु भारत सरकार को सौंपने की सिफारिश करनी चाहिए।

4. भारत के चुनाव आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने प्रस्तुत किया है कि आर.पी. अधिनियम की धारा 29 ए (5) और (7) जैसे कई प्रावधान हैं जो आयोग को दायर दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार देते हैं। किसी राजनीतिक दल को अपने पंजीकरण के समय और इस प्रकार दायर किए गए आवेदन के साथ अपना संविधान/नियम संलग्न करना होगा, जिसमें इस आशय का एक विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए कि संघ/निकाय कानून के अनुसार भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों की स्थापना और कि वे भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को कायम रखेंगे। हालाँकि, यह सुझाव दिया गया है कि चुनाव आयोग के पास एक बार पंजीकृत होने के बाद आर.पी. अधिनियम के तहत किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने/मान्यता रद्द करने की शक्ति नहीं है। एक पंजीकृत राजनीतिक दल चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 (इसके बाद "प्रतीक आदेश" के रूप में संदर्भित) के पैराग्राफ 6 ए या 6 बी में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर ही राज्य या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता का हकदार है। चुनाव आयोग, प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 16ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी राजनीतिक दल के खिलाफ आदर्श आचार

संहिता का पालन करने में विफलता पर या यदि पार्टी चुनाव के वैध निर्देशों और निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकती है। आदर्श आचार संहिता अन्य बातों के साथ-साथ कुछ दिशानिर्देश प्रदान करती है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है या आपसी नफरत पैदा कर सकता है या दो अलग-अलग जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा कर सकता है और कोई भी राजनीतिक दल वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर ऐसी अपील नहीं करेगा। इसमें आगे प्रावधान है कि किसी भी धार्मिक स्थान का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में नहीं किया जाएगा। हालाँकि, चुनाव आयोग के पास केवल आचार संहिता के अस्तित्व के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषणों को नियंत्रित करने की शक्ति है, अन्यथा नहीं।

5. भारत के विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र तैयार किया है और विभिन्न मुद्दों पर इस मामले का अध्ययन किया है कि क्या चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता से संबंधित मौजूदा प्रावधानों (संवैधानिक या वैधानिक) में संशोधन की आवश्यकता है?

विधि आयोग ने पहले अपनी 1998 की सिफारिशों में अयोग्यता से संबंधित प्रावधान को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया था और

उसके मद्देनजर, सुश्री अरोड़ा ने कहा था कि कानून में संशोधन करना और चुनाव आयोग को अधिकार देना केवल विधायिका का काम है। प्रासंगिक संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के शासनादेश का पालन करने में संतुलनकारी कार्य करें।

6. कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय सस्केचेवान (मानवाधिकार आयोग) बनाम व्हाटकॉट 2013 एससीसी 11 में, "नफरत" अभिव्यक्ति को परिभाषित करने वाले मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए "घृणास्पद भाषणों" के प्रकाशन पर नियंत्रण के लिए "मानवाधिकार दायित्वों" को सामने लाने में सफल रहा। भाषण" यह देखते हुए कि कनाडा (मानवाधिकार आयोग) बनाम टेलर, (1990) 3 एससीआर 892 में निर्धारित "घृणा" की परिभाषा, कुछ संशोधनों के साथ, "घृणा" शब्द की व्याख्या करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करती है जैसा कि विधायी में उपयोग किया जाता है। नफरत फैलाने वाले भाषण पर रोक लगाने वाले प्रावधान। तीन मुख्य नुस्खों का पालन किया जाना चाहिए। सबसे पहले, अदालतों को नफरत फैलाने वाले भाषण पर निष्पक्षकता से निषेध लागू करना चाहिए। अदालतों को यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या एक उचित व्यक्ति, संदर्भ और परिस्थितियों से अवगत होकर, अभिव्यक्ति को संरक्षित को उजागर करने के रूप में देखेगा। दूसरा, विधायी शब्द "घृणा" या "घृणा या अवमानना" की व्याख्या उन्हीं तक सीमित होने के रूप में की जानी चाहिए शब्दों द्वारा वर्णित भावना की चरम अभिव्यक्तियाँ "घृणा" और "अपमान"।

यह उस अभिव्यक्ति को फ़िल्टर करता है जो प्रतिकूल और आपत्तिजनक होते हुए भी घृणा, अवैधीकरण और अस्वीकृति के स्तर को नहीं भड़काती है जिससे भेदभाव या अन्य हानिकारक प्रभाव पैदा होने का खतरा होता है। तीसरा, न्यायाधिकरणों को अपने विश्लेषण को मुद्दे पर अभिव्यक्ति के प्रभाव पर केंद्रित करना चाहिए, अर्थात् क्या इससे लक्षित व्यक्ति या समूह को दूसरों द्वारा घृणा का सामना करने की संभावना है। व्यक्त किए जा रहे विचारों की प्रतिकूलता अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, और अभिव्यक्ति के लेखक का इरादा घृणा या भेदभावपूर्ण व्यवहार को भड़काना है या नहीं, यह अप्रासंगिक है। भेदभाव को कम करने या समाप्त करने के विधायी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अपने दर्शकों पर अभिव्यक्ति के संभावित प्रभाव को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है।

7. नफरत फैलाने वाला भाषण किसी समूह में उनकी सदस्यता के आधार पर व्यक्तियों को हाशिये पर धकेलने का एक प्रयास है। ऐसी अभिव्यक्ति का उपयोग करना जो समूह को घृणा के लिए उजागर करती है, घृणास्पद भाषण समूह के सदस्यों को बहुसंख्यकों की नज़र में अवैध ठहराने का प्रयास करता है, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज के भीतर स्वीकार्यता कम हो जाती है। इसलिए, घृणास्पद भाषण व्यक्तिगत समूह के सदस्यों को कष्ट पहुंचाने से परे होता है। इसका सामाजिक प्रभाव पड़ सकता है। नफरत फैलाने वाला भाषण बाद में कमजोर लोगों पर

व्यापक हमलों के लिए आधार तैयार करता है, जो भेदभाव से लेकर बहिष्कार, अलगाव, निर्वासन तक हो सकता है। हिंसा और, सबसे चरम मामलों में, नरसंहार तक। नफरत फैलाने वाला भाषण एक संरक्षित समूह की बहस के तहत महत्वपूर्ण विचारों पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता को भी प्रभावित करता है, जिससे हमारे लोकतंत्र में उनकी पूर्ण भागीदारी में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है।

8. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, 9 वां संस्करण 'घृणास्पद भाषण' अभिव्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित करता है:

"ऐसा भाषण जिसका किसी समूह, जैसे कि किसी विशेष जाति, के प्रति घृणा की अभिव्यक्ति के अलावा कोई अर्थ नहीं होता, विशेषकर उन परिस्थितियों में जिनमें संचार से हिंसा भड़कने की संभावना हो।"

9. रमेश बनाम भारत संघ, एआईआर 1988 एससी 775 में, विषय से निपटते समय, इस न्यायालय ने कहा:

> "..शब्दों के प्रभाव को उचित, मजबूत दिमाग वाले, दृढ़ और साहसी पुरुषों के मानकों के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि कमजोर और अस्थिर दिमाग वाले, न ही उन लोगों के जो हर शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण में खतरे को भांप लेते हैं,"

10. नफरत फैलाने वाले भाषणों के ऐसे विनाशकारी परिणामों को देखते हुए, भारतीय कानूनी ढांचे ने इस विषय से निपटने के लिए कई वैधानिक प्रावधान बनाए हैं जिन्हें निम्नानुसार संदर्भित किया गया है:

क्र.सं.	कानून	प्रावधान
1.	भारतीय दंड संहिता, 1860	धारा 124ए, 153ए, 153बी, 295-ए, 298, 505(1), 505(2)
2.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951	धारा 8, 123 (3ए), 125
3.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम, 2011	धारा 66ए, 69, 69ए नियम 3(2)(बी), नियम 3(2)(1)
4.	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973	धारा 95, 107, 144 151, 160
5.	गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967	धारा 2(एफ), 10, 11, 12
6.	नागरिक अधिकाराें का संरक्षण अधिनियम, 1955	धारा 7

7.	धार्मिक संस्थाएँ (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1980	धारा 3 आैर 6
8.	केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियम), 1994	धारा 5,6,11,12,16 17, 19, 20 एवं नियम 6 एवं 7
9.	सिनेमैटोग्रार्स अधिनियम, 1952	धारा 4, 5 बी, 7

11. इसके अलावा, केंद्र सरकार ने देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हमेशा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को कई तरीकों से सहायता प्रदान की है और जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार समय-समय पर इस संबंध में सलाह भी भेजती है। हालाँकि, ऐसे मामलों में, चूंकि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था संविधान की 7 वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है, इसलिए घृणा फैलाने वाले भाषणों में शामिल अपराधों सहित अपराध के पंजीकरण और अभियोजन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है।

12. केंद्र सरकार ने भी 2008 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि असंयमित

और भड़काऊ भाषणों और बयानों से भावनाएं भड़काने वाले और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी "सांप्रदायिक सद्भाव पर दिशानिर्देश, 2008" सांप्रदायिक गड़बड़ी/दंगों को रोकने और टालने का प्रयास करता है और ऐसी गड़बड़ी होने की स्थिति में, इसे नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई और सहायता और राहत प्रदान करने के उपाय करता है। प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। निवारक/उपचारात्मक उपाय करने और प्रशासन की ज़िम्मेदारियाँ लागू करने और उन्हें लागू करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न तौर-तरीके तैयार किए गए हैं जिनमें हितधारकों की भागीदारी पर जोर दिया गया है।

13. जहां तक वैधानिक प्रावधानों का सवाल है, जैसा कि यहां ऊपर बताया गया है, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124ए (इसके बाद 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित) राजद्रोह को दंडनीय अपराध बनाती है, यानी, जब कोई व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना या असंतोष भड़काने का प्रयास या इसमें शामिल होने का प्रयास करता है। (केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1962 एससी 955)

14. आईपीसी की धारा 153 ए और 153 बी ऐसे किसी भी कार्य को दंडनीय बनाती है जो धर्म और नस्ल आदि के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देता है या जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है। इस तरह के प्रावधान को लागू करने का उद्देश्य "विखंडनकारी सांप्रदायिक और अलगाववादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना और भाईचारे को सुरक्षित करना था ताकि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित हो सके"। निस्संदेह, धार्मिक स्वतंत्रता के साथ धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ दूसरों की धार्मिक मान्यताओं की उचित आलोचना करने की स्वतंत्रता भी हो सकती है, लेकिन जैसा कि अदालतों द्वारा बार-बार माना गया है, शक्तियों के साथ जिम्मेदारी भी आती है।

15. आईपीसी की धारा 295 ए धर्म से संबंधित अपराधों से संबंधित है और भाषण के लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान करती है। ऐसे लेख या संकेत जो किसी भी वर्ग के नागरिकों के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से बनाए गए हों। इस न्यायालय ने रामजी लाल मोदी बनाम यूपी राज्य, एआईआर 1957 एससी 620 में धारा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।

16. इसी तरह आईपीसी की धारा 298 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर और

दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया कोई भी कार्य दंडनीय है। हालाँकि, आईपीसी की धारा 295 ए कहीं अधिक गंभीर अपराधों से संबंधित है।

इसके अलावा, आईपीसी की धारा 505(2) में प्रावधान है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान देना एक दंडनीय अपराध है जिसमें तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों शामिल हैं।

17. नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955, जिसे भारत में 'अस्पृश्यता' को समाप्त करने के संवैधानिक आदेश के पूरक के लिए अधिनियमित किया गया था, में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे 'दलित' समुदायों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण को दंडित करने के प्रावधान शामिल हैं। अधिनियम की धारा 7(1)(सी) किसी भी व्यक्ति या वर्ग द्वारा किसी भी रूप में अस्पृश्यता की प्रथा को उकसाने या प्रोत्साहित करने पर रोक लगाती है (शब्दों द्वारा, चाहे मौखिक या लिखित रूप से, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा)। आम तौर पर व्यक्ति या जनता। इसी प्रकार, 'अनुसूचित जाति' और 'अनुसूचित जनजाति' के सदस्यों का जानबूझकर सार्वजनिक अपमान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दंडित किया जाता है।

18. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय, भाषा आदि के आधार पर वोट की अपील नहीं करेगा।

आर.पी.एक्ट की धारा 125 किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को ऐसे कृत्य को दंडनीय अपराध बनाकर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी या नफरत की भावना पैदा करने से रोकती है।

19. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, 1966 (आईसीसीपीआर) का अनुच्छेद 20(2) राष्ट्रीय, नस्लीय या धार्मिक घृणा की वकालत को रोकता है जिसके परिणामस्वरूप भेदभाव, शत्रुता या हिंसा भड़क सकती है और इसे कानून द्वारा निषिद्ध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

इसी प्रकार नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1965 (आईसीईआरडी) के अनुच्छेद 4 और 6 नफरत भरे भाषण के तत्वों को प्रतिबंधित करते हैं और सदस्य देशों को कानून के उपयुक्त ढांचे के माध्यम से किसी भी तरह के नफरत भरे भाषण को प्रतिबंधित करने वाला कानून बनाने का आदेश देते हैं।

20. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विधायिका ने पहले ही ऐसी गतिविधियों में लिप्त लेखक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त और प्रभावी उपाय प्रदान कर दिया था। उपरोक्त के बावजूद, याचिकाकर्ता ने

राहत की मांग की जो कानून के समान है। इस न्यायालय ने लगातार यह माना है कि हमारा संविधान स्पष्ट रूप से शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान करता है और न्यायालय केवल उस कानून को लागू करता है जो उसे विधायिका से मिलता है। नतीजतन, एंग्लो-सैक्सन कानूनी परंपरा ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायाधीशों को प्रत्याशित परिणामों, निष्पक्षता या सार्वजनिक नीति के विचारों की परवाह किए बिना केवल कानून को प्रतिबिंबित करना चाहिए और न्यायाधीश कानून बनाने के लिए अधिकृत नहीं है। "यदि कोई कानून है, तो न्यायाधीश निश्चित रूप से इसे लागू कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीश कोई कानून नहीं बना सकते हैं और न ही इसे लागू करने का प्रयास कर सकते हैं।" अदालत किसी अच्छे कारण से कानून को दोबारा नहीं लिख सकती, दोबारा नहीं बना सकती या नया स्वरूप नहीं दे सकती क्योंकि उसके पास कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। कानून बनाने का अधिकार ही न्यायालयों को नहीं दिया गया है। हालाँकि, हाल ही में, भारत में उच्च न्यायालयों की न्यायिक सक्रियता ने बार-बार लोगों की भौंहें चढ़ा दी हैं। यद्यपि न्यायिक सक्रियता को सक्रिय व्याख्या माना जाता है। संविधान के अनुसार सामाजिक बेहतरी के लिए कानून की उपयोगिता बढ़ाने की दृष्टि से मौजूदा प्रावधान की आड़ में अदालतों ने सामाजिक-आर्थिक न्याय की संवैधानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किया है। कई मामलों में, इस न्यायालय ने क़ानूनों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए विभिन्न

दिशानिर्देश/दिशा-निर्देश जारी किए, या जब यह पाया गया कि कुछ लाभार्थी प्रावधानों का अयोग्य व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था, जो पात्र व्यक्तियों को वैध दावों से वंचित कर रहे हैं। (देखें: एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य, एआईआर 1982 एससी 149; बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ एवं अन्य, एआईआर 1984 एससी 802; भारत संघ एवं अन्य बनाम देवकी नंदन अग्रवाल, एआईआर 1992 एससी 96; सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ, एआईआर 1994 एससी 268; विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, एआईआर 1997 एससी 3011: डिविजनल मैनेजर, अरावली गोल्फ क्लब और अन्य वी. चंदर हास और अन्य, (2008) 1 एससीसी 683; और सामान्य कारण (ए पंजीकृत सोसायटी) बनाम भारत संघ और अन्य, (2008) 5 एससीसी 511)।

21. नंद किशोर बनाम पंजाब राज्य, (1995) 6 एससीसी 614 में संविधान के अनुच्छेद 141 के दायरे की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

> "उनके आधिपत्य के निर्णय मौजूदा कानून की घोषणा करते हैं, लेकिन कोई नया कानून नहीं बनाते हैं, यह संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण कार्य के अनुरूप नहीं है, क्योंकि न्यायालय केवल मौजूदा कानून की

व्याख्या करने वाला नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे। राज्य की एक शाखा के रूप में न्यायालय अपने आप में कानून का एक स्रोत है। कानून वही है जो न्यायालय कहता है।"

22. जो भी हो, इस न्यायालय ने लगातार स्पष्ट किया है कि न्यायालय द्वारा निर्देश केवल तभी जारी किए गए हैं जब कानून में पूर्ण शून्यता हो, यानी बुनियादी मानव अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सक्रिय कानून की पूर्ण अनुपस्थिति हो। यदि किसी भी कारण से कार्यपालिका की ओर से निष्क्रियता होती है, तो कानून को लागू करने के लिए अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए, अदालत ने कदम उठाया है। किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए कानूनी व्यवस्था के शून्य होने की स्थिति में न्यायालय उस समय तक दोषमुक्ति प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है जब तक विधायिका इस क्षेत्र को कवर करने के लिए उचित कानून बनाकर अपनी भूमिका निभाती है। इस प्रकार, निर्देश केवल उसी स्थिति में जारी किया जा सकता है जहां निर्वाचित विधायिका की इच्छा अभी तक व्यक्त नहीं की गई है।

23. इसके अलावा, अदालत को ऐसी राहत नहीं देनी चाहिए या ऐसा आदेश/निर्देश पारित नहीं करना चाहिए जो कार्यान्वयन में सक्षम न हो। यह न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य में है। और अन्य. वि. यूपी. राज्य खनिज

विकास निगम संघर्ष समिति एवं अन्य, (2008) 12 एससीसी 675, ने निम्नानुसार आयोजित किया है:

> "48. हमारे लिए, ऐसे मामलों में विचारों में से एक यह है कि क्या पारित आदेश या जारी किया गया निर्देश कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए अतिसंवेदनशील है, और यदि इसे लागू नहीं किया जाता है तो क्या अदालत के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के लिए विपरीत पक्ष के विरूद्ध कार्यवाही सहित उचित कार्यवाही शुरू की जा सकती है। उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश इस परीक्षण में विफल रहता है और उस आधार पर भी, आदेश असुरक्षित है।" (जोर दिया गया)

24. न्यायिक समीक्षा न्यायिक संयम के सिद्धांतों के अधीन है और इसे अन्य पहलुओं में असहनीय नहीं होना चाहिए। (देखे: किंग एम्परर बनाम ख्वाजा नजीर अहमद, एआईआर 1945 पीसी 18; हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चौधरी भजन लाल और अन्य बनाम, एआईआर 1992 एससी 604; और अखिलेश यादव आदि बनाम विश्वनाथ चतुर्वेदी, (2013) 2 एससीसी 1).

25. अनुचित कार्यों पर उचित प्रतिबंध लगाना वांछनीय है लेकिन निषेध को कुछ प्रबंधनीय मानकों तक सीमित रखने में कठिनाई उत्पन्न

हो सकती है और ऐसा करने में, इसमें सभी प्रकार के भाषण शामिल हो सकते हैं जिनसे बचना आवश्यक है। लंबे समय से अमेरिकी अदालतें "घृणास्पद भाषण" और संबंधित मुद्दों पर अंकुश लगाने वाले कानूनों को बरकरार रखने में संतुष्ट थीं। हालाँकि, हाल ही में, अदालतों ने गियर बदल दिए हैं जिससे असंख्य फैसलों का मार्ग प्रशस्त हो गया है जो एक प्रबंधनीय समाज के आदेश के विपरीत भाषण और अभिव्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में हैं। [देखें: ब्यूहरनैस बनाम इलिनोइस, 343 यू.एस. 250 (1952); ब्रैंडेनबर्ग बनाम ओहियो, 395 यू.एस. 444 (1969); एवं आर.ए.वी. बनाम सेंट पॉल शहर, 112 एस. सीटी. 2538 (1992)).

26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कानून को इस आशय से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई मनमाना, अनुचित या अन्यथा किसी वैधानिक प्रावधान या दंडात्मक कानून, के उल्लंघन की कार्रवाई की जाती है, अदालत इसके समक्ष मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राहत दे सकती है और इस पर विचार करते हुए वैधानिक प्रावधान शामिल हैं। हालाँकि, अदालत को ऐसा कोई भी अप्रबंधनीय आदेश पारित नहीं करना चाहिए जो प्रवर्तन में अक्षम हो।

27. जैसा कि ऊपर बताया गया है, वैधानिक प्रावधान और विशेष रूप से दंडात्मक कानून "घृणास्पद भाषणों" के खतरे को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय प्रदान करते हैं। इस प्रकार, पीड़ित व्यक्ति को एक विशेष

क़ानून के तहत प्रदान किए गए उपाय का सहारा लेना चाहिए। समस्या की जड़ कानूनों का अभाव नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव है। इसलिए, कार्यपालिका के साथ-साथ नागरिक समाज को भी पहले से मौजूद कानूनी व्यवस्था को लागू करने में अपनी भूमिका निभानी होगी। सभी स्तरों पर "घृणास्पद भाषणों" का प्रभावी विनियमन आवश्यक है क्योंकि ऐसे भाषणों के लेखकों पर मौजूदा दंडात्मक कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है और सभी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा कानून बेकार न हो जाए। उपरोक्त प्रावधानों का प्रवर्तन "सैलस रीपब्लिका सुप्रेमा लेक्स" (राज्य की सुरक्षा सर्वोच्च कानून है) के प्रस्ताव के अनुरूप होना आवश्यक है।

28. इस प्रकार, हमें कुछ ऐसे निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए जो प्रवर्तन/निष्पादन में असमर्थ हैं। यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नफरत फैलाने वाले भाषण के कथित लेखकों के खिलाफ स्वत: संज्ञान से कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लेता है तो यह उसके अधिकार क्षेत्र में होगा।

हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विधि आयोग ने यह अध्ययन किया है कि क्या चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक दल या उसके सदस्यों को अयोग्य ठहराते हुए उसकी मान्यता रद्द करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए, यदि कोई पार्टी या उसके सदस्य संदर्भित अपराध

करते हैं यहां ऊपर, हम कानून आयोग को अनुरोध करते हैं कि यहां उठाए गए मुद्दों की भी पूरी तरह से जांच करे और यदि उचित लगे तो इसे परिभाषित करने पर भी विचार करें। अभिव्यक्ति "घृणास्पद भाषण", का खतरा, चाहे वे कभी भी दिए गए हों, पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव आयोग को मजबूत करने के लिए संसद से सिफारिशें करें। इन टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

फैसले की एक प्रति भारत के विधि आयोग के माननीय अध्यक्ष को भेजी जाए।

रिट याचिका निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री राजीव कुमार बिजलानी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।